

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

2. निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।

देहरादून, दिनांक 24 अगस्त, 2009

विषय : अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास की योजना का क्रियान्वयन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या: 125/XVII(1)/09-42(प्रकोष्ठ)/2007 दिनांक 13 फरवरी, 2009 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के सम्बन्ध में नवीन दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे। उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 13 फरवरी, 2009 के संलग्नक में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये प्रस्तर-7(3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये प्रस्तर को एतद्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

स्तम्भ-1 वर्तमान प्रस्तर	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर-7(3)
नगर क्षेत्र में इसी प्रकार रुपये 5.00 लाख तक की सीमा के कार्य सम्बन्धित नगर निकाय करेगी और उपयोगिता प्रमाण पत्र ऐसे नगर पंचायत के अध्यक्ष, एक अनुसूचित जाति के सदस्य एवं सचिव/कार्यकारी अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। नगर निगम देहरादून द्वारा योजनान्तर्गत स्वयं कराये जाने वाले कार्यों की सीमा रुपये 10.00 लाख तक होगी।	नगर क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत कार्य सम्बन्धित नगर निकाय करेगी और उपयोगिता प्रमाण पत्र ऐसे नगर पंचायत के अध्यक्ष, एक अनुसूचित जाति के सदस्य एवं सचिव/कार्यकारी अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। चूंकि नगर निकायों को परियोजना के सापेक्ष धनाबंटन की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है और नगर निकाय अपने क्षेत्र में स्वयं निर्माण कार्य करवाती है, अतः उपरोक्त प्रस्तर-6(3) के प्रावधानानुसार स्वीकृत किये गये नगरीय क्षेत्रों के कार्य संबंधित नगर निकाय द्वारा स्वयं ही करवाये जा सकेंगे। उक्त कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेंट) नियमावली, 2008 के अनुसार कराये जाने सुनिश्चित किये जायेंगे।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के सम्बन्ध में सामान्य दिशा-निर्देश सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 13 फरवरी, 2009 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 240(P)/XXVII(3)/2009, दिनांक 17 अगस्त, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(मनीषा पंवार)
सचिव एवं आयुक्त।

संख्या : 498(1)/XVIII(1)/09-42(प्रकोष्ठ)/2007 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ, पौड़ी/नैनीताल।
3. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, नैनीताल/पौड़ी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(सी. एम. एस. विष्ट)
अपर सचिव।